

[2023] 6 एस सी आर 354 ए

/

[2023] 6 एस सी आर।

/

मेसर्स लिसी मेडिकल इंस्टीट्यूट

बनाम

केरल राज्य और अन्य । (सिविल अपील संख्या 6799/2017)

/

फरवरी 09, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, न्यायाधीशगण]

केरल भवन कर अधिनियम, 1975 -धारा 3 (1)-धाराओं में निहित छूटों के प्रविधान का निर्वचन। 3(1) - लिसी चिकित्सा संस्थान बनाम केरल राज्य में दो न्यायाधीशों की पीठ ने एस. एच. चिकित्सा केंद्र अस्पताल बनाम केरल राज्य में दो न्यायाधीशों के पहले के निर्णय में निहित कुछ टिप्पणियों की शुद्धता पर संदेह किया है। केरल भवन कर अधिनियम 1975 की 3 (1) (बी), एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने उन टिप्पणियों को शामिल किया है जो सुझाव देती हैं कि धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण का अर्थ है कि एक 'धर्मार्थ उद्देश्य' केवल गरीबों की राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत तक ही सीमित है- अभिनिर्धारित किया गया: एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में दो-न्यायाधीशों की पीठ का यह विचार धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण के स्पष्ट अर्थ से सहमत नहीं है-एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में दो न्यायाधीशों की पीठ ने 'शामिल' शब्द के उपयोग को 'अर्थ' के साथ जोड़ दिया-स्पष्टीकरण यह इंगित करता है कि 'पूर्व प्रयोजन' गरीबों की राहत और मुफ्त चिकित्सा राहत तक ही सीमित नहीं है-परिणामतः, एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में निर्णय उस निर्वचन की सीमा तक जो केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) (ख) के स्पष्टीकरण पर रखा गया है, विधि की स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है-इसलिए एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में निर्णय को उपरोक्त सीमा तक खारिज कर दिया गया है। एसएच मेडिकल सेंटर अस्पताल बनाम केरल राज्य (2014)

/

/

/

/

11 एस. सी. सी. 381-निरस्त।संदर्भित निर्णय

/

(2017) 14 एस. सी. सी. 533

खारिज कर दिया गया

पैरा **1**

/

354

355

मेसर्स लिसी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाम केरल राज्य और ओआरएस।

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2017 की सिविल अपील संख्या 6799।

2016 के सी. आर. पी. सं. 1386 और 2016 के डब्ल्यू. पी. सी. सं. 20448 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

/

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. वी. मोहन, जिजो पॉल कल्लूकरन, के. वी. बालकृष्णन, राहुल कुमार शर्मा, विष्णु पी., अधिवक्तागण।अपीलार्थी के लिए।वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, रमेश बाबू एम. आर., अधिवक्तागण । उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. तीन न्यायाधीशों की पीठ का वर्तमान संदर्भ लिसी चिकित्सा संस्थान बनाम केरल राज्य 1 में दो न्यायाधीशों की पीठ के एक संदर्भ निर्णय में दिया गया है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक पूर्व निर्णय में निहित कुछ टिप्पणियों की शुद्धता पर संदेह किया है

/

एसएच मेडिकल सेंटर अस्पताल बनाम केरल राज्य 2 में दो न्यायाधीश।

2. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर बसंत और प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी गिरि को सुना है।

/

3. यह मुद्दा केरल भवन कर अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) में निहित छूट के प्रावधान की व्याख्या को सक्रिय करता है, जिसे नीचे निकाला गया है:

"3. छूट-(1) इस अधिनियम में कुछ भी निम्न पर लागू नहीं होगा

(क) केरल सरकार या भारत सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले भवन ;
और

/

((ख) इमारतें जिनका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए या कारखानों या कार्यशालाओं के रूप में किया जाता है।

स्पष्टीकरण .- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "पूर्त प्रयोजन" में गरीबों की राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत शामिल है। "

/

4. केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) का खंड (बी) निर्धारित करता है कि अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा

1 (2017) 14 एससीसी 533 2 (2014) 11 एससीसी 381

/

356

/

[2023] 6 एस सी आर।

/

उपयोग की जाने वाली इमारतें "मुख्य रूप से. धर्मार्थ. उद्देश्यों के लिए"।स्पष्टीकरण [अब स्पष्टीकरण (1)] इंगित करता है कि उप-धारा 'धर्मार्थ उद्देश्य' के उद्देश्य के लिए "गरीबों को राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत" शामिल है।स्पष्ट रूप से, इसलिए, स्पष्टीकरण इंगित करता है कि 'पूर्त प्रयोजन' अभिव्यक्ति का अर्थ गरीबों को राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत तक ही सीमित नहीं है जैसा कि 'अंतर्गत/शामिल ' अभिव्यक्ति के उपयोग से प्रमाणित होता है।जब कोई कानून 'शामिल' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, तो यह निर्वचन का सुस्थापित सिद्धांत है

कि स्पष्टीकरण का उद्देश्य व्यापक नहीं होना है।⁵ हालाँकि, केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) (ख) के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (पूर्वोक्त) की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय के पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित टिप्पणियों को शामिल किया है:

/

/

“उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 (1) के "स्पष्टीकरण" खंड की सही व्याख्या करते हुए कहा है कि "धर्मार्थ उद्देश्य" का अर्थ है "गरीबों को राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत"।

(जोर दिया गया) 6.6. उपरोक्त विचारों/निष्कर्षों से पता चलता है कि दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण का अर्थ यह समझा कि एक 'पूर्ण प्रयोजन' केवल गरीबों को राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत तक ही सीमित है। एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (पूर्वोक्त) में दो-न्यायाधीशों की पीठ का यह अवलोकन धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण के साधारण अर्थ के अनुरूप नहीं है। यह वह पहलू था जिसे ए. के. सीकरी, न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों में संदर्भित निर्णय में नोट किया गया था:

/

/

“16. ... निर्णय देने वाली पीठ के प्रति उचित सम्मान के साथ

एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल बनाम केरल राज्य, (2014) 11

एस. सी. सी. 381, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 3 के खंड 1 के स्पष्टीकरण की व्याख्या करने में यह ध्यान न देने में त्रुटि हुई है कि इसमें "शामिल" शब्द है न कि "अर्थ"। इस त्रुटि के कारण यह माना गया कि "पूर्ण प्रयोजन" का अर्थ केवल "गरीबों की राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत" है। गरीबों को राहत और मुफ्त चिकित्सा राहत पूर्ण प्रयोजन के पहलुओं में से केवल एक है और स्पष्टीकरण सरल शब्दों में स्पष्ट करता है कि वह भी एक पूर्ण प्रयोजन है। हालांकि, समावेशी परिभाषा बताती है कि गरीबों को राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत इस बारे में व्यापक नहीं है कि पूर्ण प्रयोजन का क्या अर्थ होगा। इस प्रकार, पूर्ण प्रयोजन के वास्तविक दायरे का पता लगाने के लिए, इस न्यायालय के निर्णयों पर गौर करना होगा, भले ही इस अभिव्यक्ति की जांच आयकर अधिनियम के संदर्भ में की गई हो।

/

/

/

मेसर्स लिसी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाम केरल राज्य और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

7. एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ

'शामिल' शब्द का उपयोग 'अर्थ' के साथ किया जाता है। धारा 3 (1) (क) के स्पष्टीकरण में 'शामिल' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। स्पष्ट आशय यह है कि गरीबों की राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत पूर्ण प्रयोजन की व्यापक सामग्री नहीं है।

8. इस स्तर पर, श्री वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए उत्तरदाताओं के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा, इस प्रभाव के लिए कि निर्णय में संबोधित व्याख्यात्मक मुद्दे के अलावा

/

एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ, न्यायालय

धारा 3 (1) के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया है। श्री गिरि ने धारा 3 (1) (बी) में "मुख्य रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें" अभिव्यक्ति की ओर इशारा किया और आग्रह किया कि इस वाक्यांश की व्याख्या में

/

एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में निर्णय सही है।

9. निस्संदेह, धारा 3 (1) (ख) में प्रावधान है कि अधिनियम में कुछ भी उन इमारतों पर लागू नहीं होगा जिनका उपयोग 'मुख्य रूप से' विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें 'पूर्ण प्रयोजन' भी शामिल हैं। "मुख्य रूप से" अभिव्यक्ति उस उद्देश्य का अर्थ बताती है जो प्रमुख उद्देश्य है। "मुख्य रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली" अभिव्यक्ति पर दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई व्याख्या में धारा 3 (1) में उपयोग की जाने वाली वैधानिक भाषा को देखते हुए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख उपयोग एक सहायक उपयोग से अलग प्रमुख मूल उपयोग को संदर्भित करता है।

/

/

10. स्पष्टीकरण यह इंगित करता है कि 'धर्मार्थ उद्देश्यों' में शामिल हैं और इसलिए, गरीबों की राहत और निशुल्क चिकित्सा राहत तक सीमित नहीं है। परिणामस्वरूप, केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) (ख) के स्पष्टीकरण पर रखी गई निर्वचन की सीमा तक एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (पूर्वोक्त) में निर्णय कानून में उस स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसे ऊपर स्पष्ट किया गया है।

/

इसलिए, एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल में निर्णय को खारिज कर दिया गया है

उपरोक्त सीमा। 11. वर्तमान मामले में, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील का निपटारा करते हुए, केवल एस. एच. मेडिकल सेंटर अस्पताल (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विश्वास किया है। खंडपीठ का आक्षेपित निर्णय नीचे दिया गया है: "केरल भवन कर अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लगाए गए भवन कर से छूट के लिए अपीलार्थी के दावे के संबंध में इस रिट अपील में उठाया गया मुद्दा निर्णय में उसके खिलाफ पूरी तरह से शामिल है।

/

/

358

/

[2023] 6 एस सी आर।

केंद्र अस्पताल बनाम केरल राज्य [2014 (1) के. एच. सी. 222] में सर्वोच्च न्यायालय का। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।

अपील विफल हो जाती है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। "

12. चूंकि केरल भवन कर अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है, इसलिए हमारा विचार है कि 18 जुलाई 2016 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और धारा 3 (1) की व्याख्या के आधार पर तथ्यात्मक विश्लेषण को खुला रखने के बाद निर्णय के लिए रिट अपील को उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल किया जाना चाहिए।

/

/

13. 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 20448 में 2016 की रिट अपील संख्या 1386 को तदनुसार उपरोक्त व्याख्या को देखते हुए निपटारे के लिए केरल उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया गया है।

14. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है। तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

/

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

संदर्भ ने जवाब दिया।

/

/

/

/